नईदुनिया

गर्मी से फ्रांस में एक हजार से अधिक मौतें, कई देशों में आपात स्थिति जैसे हालात

पेरिस/लंदन/मैड्रिड, एजेंसी: यूरोप इन दिनों भीषण तापलहर की चपेट में है, जहां फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, डेनमार्क, इटली और स्विट्जरलैंड सहित 16 देशों में तापमान ने कई दशक पुराने अभिलेख तोड़ दिए हैं। फ्रांस की स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार 24 से 27 जून के बीच भीषण गर्मी के कारण लगभग एक हजार अतिरिक्त लोगों की मृत्यु हुई है।

अधिकारियों के अनुसार मृतकों में अधिकांश बुजुर्ग हैं और अधिकतर मौतें घरों में हुई हैं। राजधानी पेरिस तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभावित मामले सामने आए हैं।

अनुमान के अनुसार रविवार को यूरोप में लगभग 19 करोड़ 10 लाख लोगों ने 35 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान का सामना किया। भीषण गर्मी के कारण अनेक स्थानों पर सड़कें पिघलने लगी हैं, विद्यालय बंद कर दिए गए हैं और जंगलों में भीषण आग फैल गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरोप में तापमान वैश्विक औसत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहा है, जिससे भविष्य में ऐसी तापलहरें अधिक बार और अधिक समय तक बनी रह सकती हैं।

ब्रिटेन में जून महीने के तापमान का 50 वर्ष पुराना अभिलेख लगातार तीन बार टूटा है। दक्षिणी इंग्लैंड में तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

अत्यधिक गर्मी के कारण एक हजार से अधिक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ने से कई अस्पतालों ने आपात व्यवस्था लागू कर दी है। रेलवे पटरियों के फैलने की आशंका के चलते रेलगाड़ियों की गति सीमित कर दी गई है तथा कई क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।

स्पेन में तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पिछले चार दिनों में गर्मी से 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। भीषण गर्मी और सूखे के कारण जंगलों में आग फैलने से कई क्षेत्रों को खाली कराना पड़ा है।

जर्मनी में 41.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जिसे देश के इतिहास का सर्वाधिक तापमान बताया जा रहा है। गर्मी के कारण कई राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं तथा रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। डेनमार्क में भी 37 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो वहां के इतिहास का सबसे अधिक तापमान है।

फ्रांस में 44.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बिजली व्यवस्था प्रभावित होने से हजारों घरों में विद्युत आपूर्ति बाधित रही। अत्यधिक गर्मी को देखते हुए 1,350 से अधिक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं तथा जनसुरक्षा के मद्देनजर कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं।

न्यूज ब्रीफ

प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के जश्न में

विक्टोरिया (सेशेल्स)। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को सेशेल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर राजधानी विक्टोरिया में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह के जश्न में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इस समारोह में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने सेशेल्स के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है। यह समारोह सेशेल्स की आजादी की स्वर्ण जयंती का प्रतीक है। यह अवसर पिछले पचास वर्ष में सेशेल्स के लोगों की शानदार यात्रा को एक उचित श्रद्धांजलि थी। उन्होंने कहा, भारत को सेशेल्स के विकास के सफर में एक भरोसेमंद दोस्त और साझेदार के तौर पर उसके साथ खड़े होने पर गर्व है। हमारी साझेदारी साझा मूल्यों और लोगों के बीच आपसी संबंधों के मजबूत होने के साथ और भी गहरी होती जा रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हमारी दोस्ती और भी मजबूत होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेशेल्स की आजादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित नेशनल डे के जश्न में गेस्ट आफ आनर के तौर पर शामिल हुए और ऐसा सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा, इस परेड में भारतीय नौसेना और सेना की टीमों वाली एक भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। भारतीय मार्चिंग यूनिट का हिस्सा एक भारतीय नौसेना बैंड भी रहा। यह भारत और सेशेल्स की करीबी और खास साझेदारी को दिखाता है। एक खास पहल के तहत आईएनएस तरकश और आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में खड़ा किया गया। यह सेशेल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऐतिहासिक मौके पर सेशेल्स के लोगों को भारत की ओर से शुभकामनाएं दीं।

पाकिस्तान का अफगान सीमा पर हवाई हमला, 25 आतंकियों को मारने का दावा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की संघीय सरकार ने कराची में सिंध रेंजर्स मुख्यालय पर हमले के बाद 28 और 29 जून की दरमियानी रात अफगान सीमा पर हवाई हमले कर 25 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है। सूचनामंत्री अताउल्लाह तरार ने इसकी पुष्टि की है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया एवं जनसंपर्क शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के रावलपिंडी मुख्यालय ने कहा कि यह कामयाबी खुफिया आधारित अभियान में मिली। पाकिस्तान के समाचार चैनल जियो न्यूज और दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सूचनामंत्री तरार ने एक्स पर कहा कि सुरक्षा बलों ने इस अभियान में कुल 29 आतंकवादियों को मार गिराया है। यह हमले हाल ही में पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में निर्दोष लोगों और कराची में पाकिस्तान रेंजर्स (सिंध) मुख्यालय के खिलाफ हुई आतंकवादी घटनाओं के बाद किए गए।

अब भारतीयों का ट्रंप पर भरोसा हुआ कम, 25 सालों में सबसे ज्यादा आई गिरावट

वाशिंगटन। भारतीयों का अमेरिकी सरकार पर भरोसा पिछले 25 सालों में सबसे कम हो गया है। वहीं अमेरिका के बारे में नकारात्मक राय रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। भारतीयों ने विदेशी नेताओं में सबसे ज्यादा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पसंद किया है। दुनियाभर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं है। 2026 के ग्लोबल ओपिनियन सर्वे के पुराने डेटा के मुताबिक भारतीय दुनिया के दूसरे बड़े नेताओं की तुलना में रूस के पुतिन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। व्लादिमीर पुतिन पर 51 फीसदी लोगों ने भरोसा जताया है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप 39फीसदी, इजरायली पीएम नेतन्याहू 34फीसदी, फ्रांसीसी प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों 33फीसदी, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की 29फीसदी और शी जिनपिंग छठें नंबर पर 25फीसदी लोगों के भरोसेमंद हैं। सर्वे से पता चलता है कि 45फीसदी भारतीय अमेरिका के बारे में सकारात्मक राय रखते हैं जबकि 31फीसदी की राय नकारात्मक है। यह पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा नकारात्मक रेटिंग है। सिर्फ 39फीसदी भारतीयों को भरोसा है कि ट्रंप वैश्विक मामलों में सही कदम उठाएंगे, जो 25 साल में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति पर भरोसे की सबसे कम रेटिंग है। ये आंकड़े पिछले साल की तुलना में बहुत बड़ा बदलाव है।

नेपाल में दुश्मनी भुलाकर दोस्त बनेंगे ओली-प्रचंड
बालेन शाह के डर से बदल रहे है, सारे समीकरण

काठमांडु

नेपाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है, जहां सालों तक एक-दूसरे के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रहे केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड अब फिर करीब आ रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच लगातार बातचीत चल रही है और संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही वामपंथी दलों का एक नया गठबंधन बन सकता है। यह सवाल हर किसी के मन में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सत्ता के लिए एक-दूसरे से भिड़ने वाले ये दो नेता फिर से साथ आने को तैयार हो गए राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ सत्ता की लालसा नहीं, बल्कि नेपाल की बदलती राजनीतिक परिस्थितियां और नए प्रधानमंत्री बालेन शाह का बढ़ता दबदबा है।

बालेन शाह के सत्ता में आने के बाद से पुराने नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनकी सरकार बड़े नेताओं की संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करा रही है। ऐसे में ओली और प्रचंड को लगने लगा है कि अगर वे अलग-अलग रहे तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और एकजुट होकर ही वे इस नई चुनौती का सामना कर सकते हैं। हालांकि, उनका यह गठबंधन कितने दिन चल पाएगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनका इतिहास काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। केपी शर्मा ओली, एक गरीब परिवार से उठकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, जिन्होंने कम्युनिस्ट आंदोलन के दौरान 14 साल जेल में बिताए। वह धीरे-धीरे यूएमएल के सबसे ताकतवर नेता बने और उन्हें बेहद चालाक, जिद्दी और हमेशा अपनी शर्तों पर खेलने वाला माना जाता है। भारत विरोधी नेता के तौर पर इनकी छवि बनी हुई है। दूसरी ओर, पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 10 सालों तक हिंसक माओवादी आंदोलन चलाया और 2006 में शांति समझौते के बाद राजनीति में आ गए। आज भी उनकी इमेज एक ऐसे नेता की है जो कभी भी पाला बदल सकते हैं। हालांकि, ओली और प्रचंड में एक बात कामन है कि दोनों सत्ता चाहते हैं, और इसी सत्ता के लिए वे कभी दोस्त तो कभी दुश्मन बनते रहे हैं।

उनकी दोस्ती और दुश्मनी का इतिहास काफी पुराना है। 2015 में नेपाल का नया संविधान बना और दोनों जानते थे कि अकेले लड़कर नहीं जीत सकते। ओली और प्रचंड पहली बार 2017 में साथ आए, जिसका फायदा हुआ और उन्होंने दो तिहाई बहुमत हासिल कर लिया। गठबंधन का फार्मूला था कि ढाई साल केपी ओली और ढाई साल पुष्प कमल दहल प्रचंड पीएम बनेंगे। यह प्लान सुनने में जितना अच्छा था, उतना जमीन पर लागू नहीं हो पाया। 2018 में दोनों दलों का विलय हो गया और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनी। लेकिन ओली को सत्ता का सुख इतना अच्छा लगा कि उन्होंने दहल को किनारे करना शुरू कर दिया, कैबिनेट में दहल के लोगों को कम महत्व मिला, पार्टी के फैसले भी ओली अकेले लेने लगे और दहल को पीएम भी नहीं बनने दिया। अंतत: सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी का विलय खत्म कर दिया।

दूसरी बार वे 2022 में साथ आए, लेकिन तब उनकी दोस्ती 2 महीने भी नहीं चली। दरअसल, 2022 के चुनाव में दोनों अलग-अलग लड़े और दोनों कमजोर हुए। दहल को लगा कि ओली के बिना सरकार नहीं बनेगी, लेकिन बाद में दहल ने 2 महीने बाद नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर ओली को हटा दिया और खुद पीएम बन गए। ओली को यह विश्वासघात लगा और रिश्तों में कड़वाहट आ गई। अब एक बार फिर, बालेन शाह के बढ़ते प्रभाव के कारण, सिर्फ ओली और प्रचंड ही नहीं, बल्कि दोनों दलों के कई बड़े नेता भी लगातार संपर्क में हैं। राज्य सरकारों में तालमेल, संविधान की रक्षा और साझा रणनीति जैसे मुद्दों पर बातचीत चल रही है। 28 जून को मदन भंडारी की 75वीं जयंती पर होने वाले एक कार्यक्रम में ओली और प्रचंड लंबे समय बाद एक ही मंच पर नजर आएंगे। इसे दोनों नेताओं के रिश्तों में आई नई नरमी का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। यह कार्यक्रम पब्लिक को यह संदेश देगा कि दोनों साथ हैं और उनके काडर को कम्युनिस्ट एकता फिर से बनने का मैसेज मिलेगा, साथ ही सरकार को भी चेतावनी होगी कि उसे मिलकर घेरा जाएगा।

यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस की रिफाइनरी में लगी आग, पुतिन का चुनौतियों से निपटने का दावा

मास्को/कीव

यूक्रेन ने आक्रामक रुख अपनाते हुए रूस पर ड्रोन हमला किया है। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस की तेल रिफाइनरी में आग लग गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले के कुछ घंटे बाद रविवार को सुरक्षा पक्की करने और चुनौतियों से निपटने का वादा किया।

द मास्को टाइम्स और तास की रिपोर्ट के अनुसार, कीव इन हमलों को फरवरी 2022 में शुरू हुए युद्ध के बाद से यूक्रेनी नागरिकों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर रूस के लगभग रोजाना होने वाले हमलों का उचित बदला मानता है।

पुतिन ने यूनाइटेड रशिया पार्टी के सम्मेलन में कहा, हां, हम समस्याओं को देख रहे हैं। हमें उनके बारे में पता है और हम उनका जवाब दे रहे हैं। हम निश्चित रूप से देश और अपने नागरिकों की सुरक्षा के साथ-साथ रूस की सीमाओं की अखंडता भी सुनिश्चित करेंगे।

पुतिन का यह भाषण यूक्रेन के एक ड्रोन हमले के कुछ घंटों बाद आया। इस हमले में रूस के दक्षिणी क्रास्नोडार क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक रिफाइनरी में आग लग गई। क्षेत्रीय गवर्नर वेनियामिन कोंद्रात्येव ने यह जानकारी दी। कीव ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे उन आपरेशन्स का हिस्सा बताया जो रूस की युद्ध लड़ने की क्षमता को कम करते हैं।

जेलेंस्की ने रविवार को एक्स पर कहा, क्रास्नोडार क्षेत्र में स्लाव्यांस्क तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ। यह स्थान फ्रंटलाइन से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। हमने यारोस्लाव क्षेत्र में भी एक रिफाइनरी को निशाना बनाया, जो हमारी सीमा से लगभग 700 किलोमीटर दूर है। पिछले सप्ताह यूक्रेन के हमले के कारण मास्को के दक्षिण-पूर्व में एक रिफाइनरी में भीषण आग लग गई थी। इससे राजधानी का बाहरी इलाका धुएं से भर गया था।

रूस के कब्जेवाले क्रीमिया ने शुक्रवार को प्रायद्वीप पर बढ़ते यूक्रेनी हवाई हमलों के असर को कम करने के लिए आपातकालीन स्थिति घोषित की है।

यह क्षेत्र ईंधन की कमी और बिजली कटौती से जूझ रहा है। यह स्थिति यूक्रेनी हमलों के कारण उत्पन्न हुई है।

ईरान से दुबई के लिए उड़ानें फिर शुरू होंगी, यात्रियों को मिलेगा फायदा

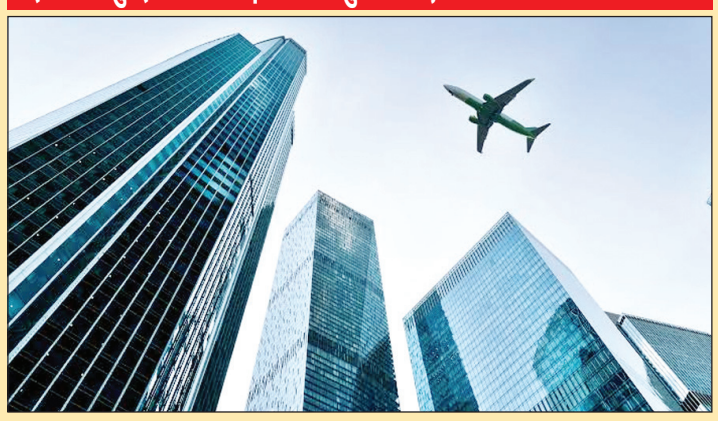

तेहरान। जंग कहीं भी हो आम आदमी के लिए परेशानी का कारण बनती है। जंग ही है जिसके कारण दुबई जाने वाले यात्री लंबे समय से उड़ाने शुरु होने का इंतजार कर रहे थे। अब उनके लिए खुशखबरी है कि ईरान से दुबई के लिए उड़ाने शुरु हो गई हैं। दोनों देशों के बीच एक जुलाई से फिर से यह सेवा बहाल होगी। ईरान के नागरिक उड्डयन संगठन के प्रवक्ता माजिद अखवान ने जानकारी दी है कि दोनों देशों के नागरिक उड्डयन संगठन ने तेहरान से दुबई के लिए उड़ानें बहाल करने की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि ईरान के विमानन अधिकारियों ने जून की शुरुआत में देश के पश्चिमी हिस्से का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। इस फैसले के पीछे इजरायल के साथ बढ़ता तनाव था। इसके बाद ईरान ने बीते मंगलवार को देश के पश्चिमी हिस्से में हवाई यात्रा बहाल करने का फैसला किया। ईरान-अमेरिका ने 18 जून की रात वर्चुअली एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच 28 फरवरी से शुरू हुए सैन्य संघर्ष को समाप्त करना है। इस समझोते में अमेरिका के समुद्री नाकेबंदी हटाने और ईरान के होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन बहाल करने की समयसीमा भी तय की गयी है। इसके अलावा ईरान ने परमाणु हथियार हासिल न करने की प्रतिबद्धता जतायी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे को अलग समझौते के जरिये सुलझाया जायेगा। दोनों पक्ष इस मामले पर 60 दिनों के भीतर बातचीत करेंगे।

पाकिस्तान का गैस संकट: ईरान से सस्ते तेल और गैस आयात की उम्मीद

इस्लामाबाद

पाकिस्तान वर्तमान में एक गंभीर गैस संकट से जूझ रहा है, जिससे उसके अधिकांश हिस्सों में उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए, अब पाकिस्तान की उम्मीदें पड़ोसी देश ईरान पर टिकी हैं, जहां से उसे सस्ते तेल और गैस आयात करने की संभावना दिख रही है। यह उम्मीद ऐसे समय में जगी है जब हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महमूद रसूल ने बताया है कि देश के कई हिस्सों में, खासकर पंजाब प्रांत में, गैस की गंभीर कमी है। स्थिति ऐसी है कि सरकार को उपभोक्ताओं को दिन में केवल कुछ घंटों के लिए ही गैस आपूर्ति करनी पड़ रही है। इस ऊर्जा संकट के कारण न केवल घरेलू उपभोक्ता बल्कि उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। हालिया घटनाक्रम में, अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों में अस्थायी तौर पर ढील दी है। उसने 60 दिनों की छूट जारी की है, जो ईरान को विशिष्ट शर्तों के तहत कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात करने की अनुमति देती है। हालांकि यह प्रतिबंधों की स्थायी छूट नहीं है और यह अमेरिका-ईरान वार्ताओं के परिणाम के आधार पर नवीनीकृत या समाप्त की जा सकती है, लेकिन इस फैसले ने ईरान से ऊर्जा आयात की संभावनाओं को खोल दिया है। इस छूट के बाद, कई हलकों से ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने की मांग उठने लगी है ताकि आम जनता को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने लाहौर में इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि ईरान-अमेरिका संघर्ष समाप्त होने के बाद खाड़ी क्षेत्र में शांति बहाल हुई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट आई है। मलिक ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान अब ईरान से सस्ते दामों में तेल और गैस आयात करने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उन्होंने यह भी दोहराया कि पाकिस्तान सरकार अंतरराष्ट्रीय समझौतों और दायित्वों के अनुसार काम करना जारी रखेगी, जिसका अर्थ है कि कोई भी आयात समझौता वैश्विक मानदंडों और संधियों के दायरे में ही होगा। मंत्री मलिक ने इस दौरान कुछ तत्वों पर पेट्रोलियम की कीमतों के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह सुनिश्चित किया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम की कम कीमतों का फायदा तुरंत जनता तक पहुंचे। अमेरिका-ईरान युद्ध के समय पाकिस्तान में पेट्रोलियम की कीमतें 414 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गई थीं, जिससे आम लोगों की जेब पर भारी बोझ पड़ा था। वर्तमान में, पेट्रोल की कीमत 300 रुपए प्रति लीटर है, जो पहले की तुलना में कुछ राहत प्रदान करती है, लेकिन गैस संकट अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ईरान से ऊर्जा आयात की संभावना पाकिस्तान के लिए न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का एक सस्ता विकल्प प्रदान कर सकती है, बल्कि भू-राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने का अवसर भी बन सकती है।

तनाव बढ़ाने वाले बयान दे रहे नेता, लाए जा रहे पुराने मुद्दे, भारत ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

ढाका

भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में पटरी पर लौटते दिख रहे रिश्तों में एक बार फिर तनाव की आशंका पैदा हो गई है। इसकी वजह बांग्लादेश के विपक्षी दल नेशनल सिटिजन्स पार्टी (एनसीपी) के ऐसे बयान हैं, जिनमें भारत से माफी मांगने की मांग की गई है, साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर भी टिप्पणी की गई है। फिलहाल, भारत की ओर से इन बयानों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब भारत ने हाल ही में बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य यात्रा वीजा जारी करने की प्रक्रिया फिर से शुरू करके दोनों देशों के रिश्तों को स्थिर करने का प्रयास किया था, जिसका ऐलान बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने पद संभालने के बाद किया था। रिपोर्ट के अनुसार, एनसीपी सांसद और विपक्ष के चीफ व्हिप नाहिद इस्लाम ने बांग्लादेशी संसद में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि भारत को आवामी लीग का 16 साल तक समर्थन करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने अभी तक बांग्लादेश के हालिया राजनीतिक इतिहास में अपनी भूमिका को स्वीकार नहीं किया है। नाहिद ने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश के अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते बराबरी और सम्मान के आधार पर होने चाहिए। उन्होंने नए भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी का नाम लेते हुए कहा, नए भारतीय उच्चायुक्त को माफी से शुरुआत करनी चाहिए। 16 सालों से भारत की सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आवामी लीग को सत्ता में रखने में मदद कर रही है और इसके लिए उसे बांग्लादेश से माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा, नाहिद ने भारत पर उस्मान हादी के हत्यारों को पनाह देने का भी आरोप लगाया और इसके लिए भी माफी की मांग की। नाहिद इस्लाम ने भारतीय सीमा बलों पर बांग्लादेशी नागरिकों की हत्या का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीएनपी सरकार के सत्ता में आने के बाद करीब 10 बांग्लादेशी भारत के सीमा सुरक्षा बल की तरफ से मारे जा चुके हैं। उन्होंने बीएनपी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम देखना चाहते हैं कि राष्ट्रवादी कही जाने वाली यह पार्टी सीमा पर हत्याओं को कैसे रोकती है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, नाहिद ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर भी गैर-जिम्मेदाराना बयानों का आरोप लगाया और बांग्लादेश सरकार तथा विदेश मंत्रालय से मजबूती से जवाब देने का आग्रह किया। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब भारत सरकार ने बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि यह दर्जा केवल रस्मी कार्यक्रमों के लिए एक व्यक्तिगत व्यवस्था के तहत दिया गया है। 25 जून को पदभार संभालने के बाद, त्रिवेदी ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य यात्रा वीजा सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। यह सेवा लगभग दो साल पहले, मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान सुरक्षा हालात बिगड़ने और नई दिल्ली के साथ संबंधों में तनाव आने के कारण रोक दी गई थी। त्रिवेदी ने बताया कि वीजा के लिए आवेदन 28 जून से ढाका, राजशाही, चटगांव, सिलहट और खुलना सहित सभी पांच केंद्रों से जमा किए जा सकेंगे, और भविष्य में इस प्रक्रिया का और विस्तार किया जाएगा।